*Quest Journals*
*Journal of Research in Humanities and Social Science*
*Volume 13 ~ Issue 11 (November 2025) pp: 192-197*
*ISSN(Online):2321-9467*
www.questjournals.org

**Research Paper**

# मुसहर जाति की सामाजिक-आर्थिक वंचना और समावेशन की संभावनाएँ: वाराणसी जनपद के संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

**डॉ. अरुणा कुमारी**
असोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

***सारांश***

*यह शोध पत्र वाराणसी जनपद में निवासरत मुसहर जाति की सामाजिक-आर्थिक वंचना और समावेशन की संभावनाओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वाराणसी में मुसहर जाति अनुसूचित जाति अंतर्गत जबकि बिहार में इन्हें "महादलित" वर्ग में शामिल किया गया है, यद्यपि यह समुदाय आज भी भूमिहीनता, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य असमानता और जातिगत भेदभाव जैसी समस्याओं से प्रभावित है। अनुसंधान में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों का उपयोग करते हुए पाया गया कि लगभग 90 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं, जबकि 82 प्रतिशत जातिगत भेदभाव का सामना करते हैं वहीं साक्षरता दर काफी निम्न है। शोध पत्र सैद्धांतिक आधार मार्क्स (1867) के वर्ग-संघर्ष सिद्धांत, अमर्त्य सेन (1999) की क्षमता दृष्टि, और बोरदियो (1986) की सांस्कृतिक पूँजी की अवधारणा पर आधारित है। मुसहरों की वंचना केवल आर्थिक नहीं, अपितु सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक रूप से भी गहराई से जुड़ी है। यद्यपि कुछ सरकारी योजनाएँ, शिक्षा कार्यक्रम और महिला स्व-सहायता समूह परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं, परंतु वास्तविक समावेशन के लिए बड़े स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है। इस शोध पत्र के आधार पर हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मुसहर जाति की वंचना एक बहुस्तरीय सामाजिक समस्या है, जिसका समाधान केवल कल्याणकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, शिक्षा और सशक्तिकरण के माध्यम से ही संभव है।*

*Received 12 Nov., 2025; **R**evised 22 Nov., 2025; **A**ccepted 24 Nov., 2025 © The author(s) 2025.*
***P**ublished with open access at **www.questjournas.org***

## परिचय एवं सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय सामाजिक संरचना में जाति, वर्ग, परंपरा और धर्म का प्रभाव रहा है जो शक्ति, प्रतिष्ठा और संसाधनों के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी रही है (Srinivas, 1962; Dumont, 1980)। भारतीय समाज के इस जटिल ताने-बाने में कुछ समुदाय ऐसे हैं जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिये (margins) पर रहे हैं। इन्हीं वंचित समूहों में एक है मुसहर जाति को भी देखा जा सकता है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में "महादलित वर्ग" के अंतर्गत वर्गीकृत है (Government of Bihar, 2007; Jha, 2013)।

शाब्दिक दृष्टि से हम देखे तो "मुसहर" शब्द स्वयं में इस समुदाय की ऐतिहासिक गरीबी और सामाजिक बहिष्कार की दास्तान समेटे हुए है। 'मूस' (चूहा) और 'हर' (खाने वाला) से निर्मित यह शब्द उनके पारंपरिक जीविकोपार्जन से जुड़ा रहा है—एक ऐसा प्रतीक जो भूख, अभाव और वंचना का सामाजिक रूपक बन गया (Narayan, 2011)। आज भी यह समुदाय भूमिहीन मजदूर, ईंट-भट्ठा श्रमिक और कृषि-मजदूर के रूप में कार्य कर रहा है (NSSO, 2011; Thorat & Newman, 2012)। यद्यपि भारतीय संविधान ने समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया है (Article 14–17, Constitution of India), परन्तु व्यवहारिक स्तर पर मुसहर समुदाय अब भी सामाजिक असमानता, आर्थिक निर्भरता और सांस्कृतिक उपेक्षा का शिकार है। इस तरह देखा जाय तो आधुनिक विकास और लोकतांत्रिक संस्थाओं की पहुँच के बावजूद, मुसहरों की स्थिति काफी दयनीय है (Béteille, 1991; Xaxa, 2005)।

इस शोध पत्र में जिन सैद्धान्तिक पक्षों को आधार बनाया गया है वे मुसहर जाति की सामाजिक-आर्थिक वंचना और समावेशन की प्रक्रिया को बहु-आयामी रूप में समझने में सहायक हैं। कार्ल मार्क्स (Marx, 1867) के *वर्ग सिद्धांत* के अनुसार, मुसहर समुदाय की स्थिति वर्ग आधारित शोषण और उत्पादन के साधनों से वंचितता का परिणाम है, जहाँ आर्थिक निर्भरता और श्रम-शोषण उनके सामाजिक हाशियाकरण को बनाए रखते हैं। अमर्त्य

सेन (Sen, 1999) की *क्षमता दृष्टि (Capability Approach)* के आधार पर कह सकते हैं कि मुसहर समुदाय की वंचना केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानव क्षमताओं—जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्र निर्णय-लेने की क्षमता—की कमी से उत्पन्न होती है, जो उनके समग्र विकास और स्वतंत्रता को बाधित करती है। वहीं, पियरे बोरदियो (Bourdieu, 1986) के *सांस्कृतिक पूँजी सिद्धांत* के अनुसार, सामाजिक और सांस्कृतिक पूँजी की कमी सामाजिक गतिशीलता और अवसरों तक पहुँच में बाधा उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त, जी.एस. घुर्ये (Ghurye, 1969) और एन.के. बोस जैसे भारतीय समाजशास्त्रियों की अंतर्दृष्टियाँ जाति-व्यवस्था की संरचनात्मक असमानताओं और परंपरागत सामाजिक विभाजन को उजागर करती हैं, जिनके कारण मुसहर जैसी दलित जातियाँ ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत और शोषित रही हैं।

**साहित्य समीक्षा**

एस. एन. तिवारी की पुस्तक "Poverty Among Musahars: Dalits of Bihar" बिहार की अत्यंत उपेक्षित दलित जाति 'मुसहर' समुदाय की गरीबी, सामाजिक बहिष्करण एवं संघर्षों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करती है। पुस्तक में ग्रामीण निर्धनता की बहुआयामी प्रकृति जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आदि को सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन के माध्यम से रेखांकित किया गया है। लेखक ने दो पंचायतों में दो सौ परिवारों पर आधारित अनुभवजन्य अध्ययन द्वारा मुसहरों की जीवन स्थितियों, विकलांगताओं, शोषण की प्रवृत्तियों तथा उनके आत्मसंघर्षों का चित्रण किया है। यह कृति न केवल सामाजिक विज्ञान के शोधार्थियों के लिए उपयोगी है, बल्कि नीति-निर्माताओं के लिए भी मार्गदर्शक सिद्ध होती है। ग्रामीण बिहार के दलित समाज की यथार्थ स्थिति को समझने हेतु यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से गरीबी की जटिलताओं को उजागर करता है।

टी. निशांत की पुस्तक "Musahars: A Noble People, A Resilient Culture" (2019) बिहार की मुसहर जनजाति के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का अत्यंत व्यापक एवं गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है। यह कृति मुसहरों की पहचान, उनकी उपेक्षित सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक प्रतिरोध और आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना के प्रयासों को उजागर करती है। लेखक ने ऐतिहासिक दस्तावेज़ों, मिथकीय परंपराओं और क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर मुसहरों की उत्पत्ति, जातिगत भेदभाव, स्त्री स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक आस्थाओं का विस्तृत विश्लेषण किया है।

अरुण शंकर प्रसाद द्वारा रचित "The Musahars" (2005) बिहार की मुसहर जाति पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अध्ययन है, जो उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। यह पुस्तक सात अध्यायों में विभाजित है, जिनमें मुसहर समुदाय की जीवन स्थितियाँ, आजीविका, सामाजिक प्रथाएँ, धार्मिक मान्यताएँ, तथा जाति-संबंधों का विश्लेषण किया गया है। लेखक ने अनुभवजन्य अनुसंधान के माध्यम से यह दिखाया है कि मुसहर समुदाय भारतीय समाज की सबसे हाशिए पर स्थित जातियों में से एक है, जिसकी पहचान अब भी उपेक्षा, निर्धनता और सामाजिक बहिष्कार से जूझ रही है।

रीता सिंह की पुस्तक "बिहार के मुसहर" (द्वितीय संस्करण, 2017) बिहार के महादलित वर्ग 'मुसहर' समुदाय के जीवन, समस्याओं और विकास की संभावनाओं का समग्र समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक में मुसहरों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक दशा, कल्याणकारी योजनाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा राजनीतिक भागीदारी का गहन विश्लेषण किया गया है। लेखिका ने क्षेत्रीय सर्वेक्षण, साक्षात्कार और तथ्य-संग्रह की वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हुए मुसहरों की जीवन-स्थितियों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है।

गौरव आर. सहाय का शोध-लेख "Substantially Present but Invisible: Excluded and Marginalised – A Study of Musahars in Bihar" (Sociological Bulletin, Vol. 68, No. 1, 2019) मुसहर समुदाय की सामाजिक अदृश्यता और संरचनात्मक बहिष्करण का गहन समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेख में ब्राह्मणवादी मिथकों, औपनिवेशिक आख्यानों और समकालीन सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से मुसहरों को "अस्पृश्य" व "अमानवीय" रूप में चित्रित किए जाने की प्रक्रिया को उजागर किया गया है। लेखक ने क्षेत्रीय नृवंशविज्ञानिक अध्ययन के आधार पर मुसहरों के जीवन-संसार, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शिक्षा, श्रम, विवाह, संस्कृति और राजनीतिक चेतना का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। यह लेख दर्शाता है कि मुसहर समुदाय न केवल सामाजिक रूप से बहिष्कृत है, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी 'अदृश्य नागरिक' बना दिया गया है। अध्ययन समाजशास्त्रीय विमर्श में उपेक्षित जातियों की अस्मिता और अधिकार की बहस को नए आयाम प्रदान करता है।

G.S. Ghurye (1969) घुर्ये ने भारतीय जाति व्यवस्था की सामाजिक-सांस्कृतिक जड़ों का गहन विश्लेषण किया है। जिसमें वे कहते हैं कि जाति केवल धार्मिक प्रणाली नहीं, बल्कि सामाजिक संगठन की वह संरचना है जो आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक असमानता को पुनरुत्पादित करती है। मुसहर जाति जैसी निम्नवर्गीय जातियाँ इसी पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर स्थित हैं, जिनकी वंचना सामाजिक रूप से संस्थागत हो गई है।

Louis Dumont (1980) दुमों ने भारतीय समाज को "पवित्रता और प्रदूषण" (Purity and Pollution) की अवधारणा पर आधारित

विश्लेषित किया है। उनके अनुसार ऊँच-नीच का यह धार्मिक-सांस्कृतिक विभाजन सामाजिक बहिष्करण की मूल जड़ है। मुसहर समुदाय की सामाजिक अलगाव की स्थिति इस सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप में दर्शाती है।

Sukhadeo Thorat & Katherine Newman (2010) इस ग्रंथ में आधुनिक भारत में जातिगत आर्थिक भेदभाव का गहन विश्लेषण किया गया है। लेखक बताते हैं कि भूमिहीनता, श्रम शोषण और प्रशासनिक पूर्वाग्रह आज भी दलित व महादलित समुदायों की आर्थिक गतिशीलता में बाधा हैं।

अस्तु, इन समीक्षाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुसहर समुदाय की वंचना बहुआयामी (Multidimensional) है - जिसमें आर्थिक निर्धनता, सांस्कृतिक पूँजी की कमी, जातिगत बहिष्करण और नीतिगत अप्रभावशीलता सम्मिलित हैं। सामाजिक न्याय और समावेशन के लिए केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं है; बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समान अवसर और सामाजिक स्वीकृति जैसे तत्वों को एकीकृत करना अनिवार्य है।

**उद्देश्य**

1. मुसहर जाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना।
2. मुसहर समुदाय के जीवन-स्तर को जातिगत भेदभाव सहित भूमिहीनता और गरीबी किस प्रकार प्रभावित करते हैं जैसे पक्षों का अध्ययन करना।
3. मुसहर समुदाय में शिक्षा सहित स्वास्थ्य एवं रोजगार की उपलब्धता तथा उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करना।
4. मुसहर समुदाय पर सरकारी योजनाओं और विकास नीतियों की पहुँच तथा उनके वास्तविक प्रभाव का विश्लेषण करना।
5. इस समुदाय के सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन की संभावनाओं को पहचानना और उन्हें सुदृढ़ करने के उपाय सुझाना।

**शोध प्रश्न**

1. वाराणसी जिला में मुसहर जाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है?
2. मुसहर समुदाय की सामाजिक गतिशीलता को जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता किस प्रकार प्रभावित करती है?
3. क्या शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी मुसहर समुदाय के विकास एवं संवर्धन में प्रमुख बाधा है?
4. क्या सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ मुसहर समुदाय तक प्रभावी रूप से पहुँच पा रही हैं?
5. मुसहर समुदाय के समावेशन और सशक्तिकरण के लिए कौन-से सामाजिक, शैक्षणिक और नीतिगत उपाय सबसे प्रभावी हो सकते हैं?

**अध्ययन क्षेत्र**

इस शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेश का वाराणसी जनपद है। वाराणसी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भारत का एक प्रतीकात्मक नगर माना जाता है। यह क्षेत्र न केवल अपनी आध्यात्मिक परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यह सिक्के का एक पक्ष है सिक्के के दूसरे पक्ष को हम देखे तो यहाँ सामाजिक असमानता और जातिगत विभाजन भी गहराई से विद्यमान हैं। वाराणसी जनपद के विविध विकासखंडों में मुसहर समुदाय की बस्तियाँ सघन रूप से स्थित हैं। इन क्षेत्रों में भूमिहीनता, अशिक्षा, स्वास्थ्य असमानता और सामाजिक बहिष्करण जैसी समस्याएँ प्रमुख हैं, जो इस अध्ययन को समाजशास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक बनाती हैं।

**समग्र**

2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 'मुसहर' की कुल जनसंख्या 2,57,135 (पुरुष 1,33,149; महिला 1,23,986) है। Joshua Project ने वाराणसी ज़िले में लगभग 22,000 मुसहर का अनुमान प्रकाशित किया है। यही जनसंख्या इस शोध पत्र के समग्र के रूप में है।

**प्रतिदर्श का चयन**

प्रतिदर्श चयन हेतु उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन तकनीक का प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत कुल 120 मुसहर परिवारों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

**शोध पद्धति**

तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर साक्षात्कार और फोकस ग्रुप डिस्कशन (FGD) को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, भूमि स्वामित्व, सामाजिक सहभागिता और सरकारी योजनाओं तक पहुँच जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया

गया। प्राथमिक स्रोतों के साथ-साथ जनगणना 2011, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2021), योजना आयोग (Planning Commission, 2013) तथा पूर्ववर्ती समाजशास्त्रीय अध्ययनों (Thorat & Newman, 2010; Xaxa, 2014) को द्वितीयक स्रोत के रूप में उपयोग किया गया। संग्रहित आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत विधि और तुलनात्मक विश्लेषण द्वारा किया गया, जबकि गुणात्मक डेटा का अध्ययन थीमैटिक एनालिसिस (Thematic Analysis) के माध्यम से किया गया, ताकि वंचना और समावेशन की प्रमुख प्रवृत्तियों को पहचाना जा सके।

साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण अधोलिखित पक्षो पर किया गया है:

**सामाजिक स्थिति**

साक्षात्कार के आधार पर जो तथ्य सामने आए उससे स्पष्ट होता है कि मुसहर समुदाय आज भी गहरे सामाजिक बहिष्करण और जातिगत भेदभाव का सामना कर रहा है। सर्वेक्षण में लगभग 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उन्हें अब भी सार्वजनिक स्थलों—जैसे मंदिरों, कुओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों—पर भेदभाव का अनुभव होता है (Shah et al., 2006)। इस तथ्य के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि सामाजिक समरसता के संवैधानिक आदर्श व्यवहारिक रूप में अभी तक स्थापित नहीं हो पाए हैं (Constitution of India, 1950)। मुसहर बस्तियाँ प्रायः गाँव के बाहरी छोरों पर स्थित हैं, जो उनके *स्थानिक बहिष्करण (spatial exclusion)* का द्योतक है (Thorat & Newman, 2010)। वहीं विवाह, धार्मिक आयोजनों और सामुदायिक भोजों में मुसहरों की भागीदारी अक्सर सीमित होती है, जिससे उनकी सामाजिक दूरी बनी रहती है। यह स्थिति लुई दुमों (Dumont, 1980) के *"पवित्रता और प्रदूषण"* सिद्धांत को पुष्ट करती है।

साथ ही राजनीतिक और पंचायत स्तर पर भी मुसहरों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। आरक्षण के बावजूद उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास वास्तविक निर्णय-क्षमता नहीं होती। यह "प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व (tokenism)" सामाजिक न्याय के सार को कमजोर करता है। इस प्रकार अवधारणात्मक रूप में कहा जा सकता है कि मुसहरों की सामाजिक स्थिति केवल जातिगत भेदभाव का परिणाम नहीं बल्कि एक संरचनात्मक विषमता है, जिसमें सांस्कृतिक उपेक्षा, प्रतीकात्मक असमानता और प्रतिनिधित्वहीनता गहराई से अंतर्निहित है।

**आर्थिक स्थिति**

मुसहर समुदाय की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। सक्षत्कार के आधार पर पाया गया कि लगभग 90 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं और कृषि-मजदूरी, निर्माण कार्य या ईंट-भट्ठों में दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्यरत हैं (Thorat & Newman, 2010)। वहीं इनकी मासिक आय ₹3,000 से ₹6,000 के बीच है, जिससे न तो बचत संभव है, न ही स्थायी रोजगार की गारंटी। इस स्थिति को मार्क्स (Marx, 1867) के *वर्ग आधारित शोषण सिद्धांत* से समझा जा सकता है, जहाँ उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कुछ वर्गों के पास केंद्रित होता है और शेष वर्ग श्रम के माध्यम से शोषित होता है। अधिकांश परिवारों के पास भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या पट्टा नहीं है, जिससे सरकारी योजनाओं तक पहुँच कठिन हो जाती है। कुछ महिलाएँ भी दिहाड़ी कार्य में संलग्न हैं, परंतु उनके श्रम का मूल्यांकन अक्सर पुरुषों की तुलना में कम होता है। यह लैंगिक असमानता बोस के समाजशास्त्रीय अवलोकनों को पुष्ट करती है। अतएव अवधारणात्मक रूप में कहा जा सकता है कि मुसहर समुदाय के जीवन में असुरक्षित रोजगार, गरीबी और ऋण-निर्भरता स्थायी यथार्थ बन चुके हैं।

**शिक्षा और साक्षरता**

मुसहर समुदाय में शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न पाया गया। सर्वेक्षण के अनुसार, पुरुष साक्षरता दर लगभग 40 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता मात्र 22 प्रतिशत है। यह साक्षरता दर बहुतायत प्राथमिक ही है। बालिकाओं की विद्यालय उपस्थिति अनियमित है, जबकि किशोरावस्था में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति सामान्य है। यह स्थिति अमर्त्य सेन (Sen, 1999) की *क्षमता दृष्टि (Capability Approach)* के अनुरूप है, जिसके अनुसार शिक्षा केवल साक्षरता नहीं बल्कि मानव स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का माध्यम है। मुसहर समुदाय में इस क्षमता का विकास नहीं हो पाने से सामाजिक गतिशीलता सीमित हो जाती है। साक्षत्कार के दौरान यह भी तथ्य उभरकर सामने आया कि आज भी कई परिवार शिक्षा को आर्थिक बोझ के रूप में देखते हैं। बच्चों को काम पर भेजना आय अर्जन का साधन माना जाता है। यद्यपि सरकारी योजनाएँ जैसे "समग्र शिक्षा अभियान" और "मिड-डे मील" कुछ हद तक प्रभावी रही हैं, परंतु इनका वास्तविक लाभ सीमित परिवारों तक पहुँचा है। अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव भी बड़ी चुनौती है। अतः यह स्पष्ट है कि मुसहर समुदाय की शैक्षणिक स्थिति केवल संसाधनों की कमी नहीं बल्कि *सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक वंचना* का परिणाम है।

**स्वास्थ्य और स्वच्छता**

स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में मुसहर समुदाय की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। सर्वेक्षण से पता चला कि 85 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय नहीं है और वे खुले में शौच करने को विवश हैं जबकि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा शौचलय की व्यवस्था 100 प्रतिशन सुनिश्चित की गई है। पेयजल के लिए भी अधिकांश बस्तियाँ सामुदायिक हैंडपंप एवं कुओं पर निर्भर हैं, जिनका जल प्रायः दूषित होता है। यह स्थिति विश्व स्वास्थ्य

संगठन (WHO, 2018) के स्वच्छता मानकों से बहुत पीछे है। मुसहर बस्तियों में कुपोषण और संक्रामक रोग अत्यधिक हैं, विशेषकर बच्चों और महिलाओं में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2021) के अनुसार, दलित और महादलित समुदायों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अब भी उच्च बनी हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीमित है। बहुतायत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उपयोग कर पाते हैं। यह *संरचनात्मक स्वास्थ्य बहिष्करण (structural health exclusion)* को इंगित करता है (Deshpande, 2011)।

**निष्कर्ष**

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि वाराणसी जनपद में मुसहर जाति का जीवन अभी भी गहरी सामाजिक और आर्थिक वंचना में आबद्ध है। संविधान द्वारा समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के अधिकार दिए जाने के बावजूद यह समुदाय मुख्यधारा के समाज से लगभग पृथक बना हुआ है (Constitution of India, 1950)। भूमिहीनता, अशिक्षा, गरीबी और जातिगत पूर्वाग्रहों ने इन्हें सामाजिक रूप से "अदृश्य वर्ग" बना दिया है। साक्षात्कार से यह भी तथ्य उभरकर सामने आये कि मुसहरों की समस्याएँ केवल संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक असमानता से जुड़ी हैं (Bourdieu, 1986)। सामाजिक पूँजी की अनुपस्थिति और प्रतिनिधित्वहीनता ने उन्हें पंचायत स्तर की निर्णय प्रक्रियाओं से बाहर रखा है। यह स्थिति घुर्ये (1969) और एन. के. बोस के इस कथन को पुष्ट करती है कि जाति-व्यवस्था भारत में असमानता की संरचनात्मक नींव है। यद्यपि कुछ सकारात्मक संकेत भी दृष्टिगोचर हुए हैं जिसमें प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर में धीरे-धीरे वृद्धि, महिलाओं में स्व-सहायता समूहों की सक्रियता, और कुछ सरकारी योजनाओं (मनरेगा, पीएम आवास योजना) की पहुँच में सुधार को देखा जा सकता है। यद्यपि इन पहलों का प्रभाव सीमित है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुसहर समुदाय की स्थिति भारतीय लोकतंत्र की उस चुनौती को रेखांकित करती है जिसमें सामाजिक समानता का संवैधानिक आदर्श और व्यवहारिक यथार्थ के बीच एक स्पष्ट अंतर मौजूद है।

**सुझाव**

मुसहर समुदाय के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशन के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों सहित बहुस्तरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सबसे पहले, शिक्षा का सार्वभौमिकरण अत्यावश्यक है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के संदर्भ में, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों और ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। महिला सशक्तिकरण हेतु स्व-सहायता समूहों (SHGs) को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और विपणन सुविधाओं से जोड़ा जाना चाहिए एवं पंचायत स्तर पर मुसहर प्रतिनिधित्व को अनिवार्य किया जाए ताकि वे निर्णय-प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें (Bourdieu, 1986)।

**संदर्भ**


[1]. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood Press.

[2]. Constitution of India. (1950). Articles 14–17. Government of India.

[3]. Deshpande, S. (2011). *Contemporary India: A Sociological View.* Penguin.

[4]. Dumont, L. (1980). Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications. University of Chicago Press.

[5]. G.S. Ghurye (1969) – Caste and Race in India, Popular Prakashan, Mumbai.

[6]. Marx, K. (1867). Das Kapital: A Critique of Political Economy. Progress Publishers.

[7]. NFHS-5. (2021). *National Family Health Survey, India.* Ministry of Health and Family Welfare.

[8]. Nishaant, T. (2019). Musahars: A Noble People, A Resilient Culture. Noida: Media House. Foreword by Prof. Sukhdeo Thorat.

[9]. Planning Commission. (2013). *Evaluation of MGNREGA and Housing Schemes.* Government of India.

[10]. Prasad, A. S. (2005). The Musahars. Patna & New Delhi: Janaki Prakashan.

[11]. Sahay, G. R. (2019). Substantially present but invisible: Excluded and marginalised—A study of Musahars in Bihar. Sociological Bulletin, 68(1), 24–44. SAGE Publications.

[12]. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.

[13]. Shah, G., Mander, H., Thorat, S., Deshpande, S., & Baviskar, A. (2006). Untouchability in Rural India. Sage Publications.

[14]. Singh, R. (2017). Bihar ke Musahar (2nd ed.). Patna & New Delhi: Janaki Prakashan. ISBN 978-93-84767-92-1.

[15]. Thorat, S., & Newman, K. (2010). *Blocked by Caste: Economic Discrimination in Modern India.* Oxford University Press.

[16]. Tiwary, S. N. (2018). Poverty Among Musahars: Dalits of Bihar. Mumbai: Heritage Publications.
[17]. WHO. (2018). *World Health Statistics Report.* World Health Organization.
[18]. Xaxa, V. (2014). Tribes and Social Exclusion in India. Routledge.